



एक नजर

लालगंज मामले के खुलासे की मांग: सौपा ज्ञापन



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। लालगंज थाना क्षेत्र के सिद्धनाथ गांव में मासूम बालिका की हत्या, दुराचार मामले के खुलासा की मांग को लेकर भीम युवा वाहिनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौपा राव, प्रदेश अध्यक्ष अजय राव उर्फ प्रमोद के नेतृत्व में पीड़ित के पिता के साथ गुरुवार को भूख हड़ताल के लिये पहुंचे। एडमिशन एसपी ने उन लोगों को संज्ञापन लेकर आश्वासन दिया कि भूख हड़ताल का दिनांक का शीघ्र खुलासा करा दिया जायेगा।

सौपा राव, अजय राव उर्फ प्रमोद आदि ने लालगंज पुलिस कारम बालिका की हत्या मामले का खुलासा कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग किया। कि कहा कि पुलिस ने डीएनए टेस्ट नहीं लिया किन्तु न्याय नहीं मिला। उल्टे न्याय की मांग करने पर पुलिस द्वारा एटीडीएन की कार्रवाई किया जाता है। ज्ञापन देने के दौरान मीन युवा वाहिनी के मंडल अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद, सौपा राव, इन्द्रावती, रीता देवी आदि शामिल रहे।

मकान कब्जा करने की साजिश, एसपी से लगाया न्याय की गुहार



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। कलवारी थाना क्षेत्र की हाल मुकाम सिद्धनाथ गांव निवासी निवासी पत्नी टिनोही लाल ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया है। एसपी को दिये पत्र में विचारणीय है कि यह मुकदमा थाना क्षेत्र के हलारी नगरा की पुलिस निवासी है। उसकी मां लालगंजी देवी पत्नी स्वर्गीय बरसाती के मकान व आराजी पर पंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर काबिज है। लेखपाल ने गणेश पुत्र विश्राम से नाराजिय लाल देव गलत दंग से नजरानी बना दिया और उसका नाम न पत्र करके एक अलग नाराजी को बाबा सत्तोषी के साथ रहती थी उसका नाम बाल दिया। विवादायित मायके में रहती है इसलिए गणेश पुत्र विश्राम को अपायक पत्र पर कार्यरत है अपनी देवगंज व धन के बल पर लेखपाल को साजिश में करके घरीनी में पियारी का नाम गलत दंग से दर्ज करा दिया। गत 24 अगस्त को गणेश ने कहा कि यह मकान छोड़ दो यह मेरी माता सावित्री उर्फ सवारी के नाम हो गय है। उल्टा कुच नहीं है। विवादायित है इसकी सूचना थाने पर दिया। डीएम को पत्र लिखा, पुलिस ने उसे पुन: मकान में कब्जा दिवावया किन्तु धन पर रखा उल्टे अदि को गायब करा दिया। शिकायत करने पर मारा पीटा।

विवादायित ने एसपी से मांग किया है कि कलवारी पुलिस को निर्देशित किया जाय कि उसके जान माल और सम्पत्ति की रक्षा करने के साथ ही न्याय दिलाया जाय।

सोनम वांगचुक के एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द

लेह (आम)। सरकार ने लद्दाख के मुख्य कार्यकारी सोनम वांगचुक द्वारा संचालित गैर-लामकारी संगठन (एनजीओ) का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया है। इसका कारण सोनम वांगचुक के लिए निर्धारित विदेशी फंडिंग संबंधी कानूनों का 'बार-बार' उल्लंघन बताया गया है। यह फैसला वांगचुक के नेतृत्व में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर मड़के हिंसक आंदोलनों के बीच 24 घंटे बाद किया गया है। हालांकि अभी एक वांगचुक की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है।

मातलब है कि केंद्रीय अन्वेषण

बाबू शिव गुलाम शहीद स्थल पर चला स्वच्छता अभियान



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। गुरुवार को 17 सितम्बर से 25 अक्टूबर तक चलने वाले सेंपा पखवाड़ा अभियान के की कड़ी में साफ़ता विकास के ग्राम पंचायत पैडा के बाबू शिव गुलाम जी के शहीद स्थल पर पुष्प अर्पित कर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई किया गया। साफ़ता डिविजन के वृक्ष प्रमुख अभिषेक कुमार ने बताया कि स्वच्छता अभियान ने पूर्व जागरूकता रैली निकाली थी, इसके बाद बाबू शिव गुलाम जी के शहीद स्थल पर साफ-सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। कहा

हमन्त दास महाराज का फूल मालाओं से स्वागत



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। गुरुवार को अधोघटा 8 आम से चलकर परम्परागत हेमन्तदास जी महाराज सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के पुजारी हेमन्त दास महाराज का पैदा वाले बाबा गोविन्द महाराज जी के नेतृत्व में बड़े वन के निकट फूल मालाओं के साथ नया स्वागत किया गया। वे एक धार्मिक आभोजन में हिस्सा लेते महाराज जा रहे थे। पुजारी हेमन्त दास महाराज ने उपस्थित लोगों से सततान धर्म की मजबूती का आवाहन किया। कहा कि नररात्रि पूर्व पर लोगों तक सततान का संदेश पहुंचाया जाय।

पुजारी हेमन्त दास महाराज का स्वागत करने वालों ने मुख्य रूप से अंतराष्ट्रीय हिंदू, परिषद जिला अध्यक्ष स्नेह पाण्डेय राष्ट्रीय बजरद दल जिला अध्यक्ष मनमोहन त्रिपाठी, आकाश आर, संदीप पाण्डेय, वरिष्ठ मुक्ति दीपक, राज आर, बहदेव पाण्डेय, विनोद निषाद, राज, सुनील, सुनील, चौहान प्रिंस सिधानिया, शनि, दुर्गा, अमर राज, अमिल, अनीश, सततान के साथ ही अनेक विशिष्ट जन शामिल रहे।

विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर संगोष्ठी में विमर्श

नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करने की मांग



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। गुरुवार को अर्द्ध इण्डिया फार्मासिस्ट फेडरेशन द्वारा प्रेष वक्तव्य समाचार में विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राबिंद्र आनी सिद्धदीकी ने फार्मासिस्टों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुये कहा कि सरकार प्रदेश के प्रशिक्षित फार्मासिस्टों को अवसर दे तो स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने से बाधाया जा सकता है। एक तरफ तो सरकार संविदा के चिकित्सकों से जैसे-तैसे काम चला रही है वहीं लगभग तीन लाख 70 हजार से अधिक फार्मासिस्ट बेरोजगार है। उन्हें तत्काल सेवाओं से जोड़कर स्थितियों को संभाला जा सकता है। फार्मासिस्टों को प्रशिक्षण देकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के रूप में उनकी योग्यता की जाय जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुधारा जा सके। कहा कि 2007 के बाद से अभी तक नियुक्तियां न निकालकर सरकार फार्मासिस्टों के हितों की खुली अनदेखी कर रही है। यदि शीघ्र समस्याओं का समाह

(एचआईएल) पहुंची थी, जिसमें गृह मंत्रालय की शिकायत पर एफसीआरए उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई का उल्लेख था।

वरसून, सोनम वांगचुक पर आरोप है कि उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए गैर-जागरूकी संस्था के एफसीआरए खाते में 3.35 लाख रुपये जमा कर दिए। एफसीआरएएल ने स्पष्ट किया कि यह शक्ति एक पुरानी बस की बिक्री से प्राप्त हुई थी। संस्था ने बवाल में कहा कि वृत्ति बस एफसीआरए फंड से खरीदी गई थी, इसलिए बिक्री की आय को उनी खाते में वापस जमा कर दिया गया। हालांकि, सरकार ने इस तर्क को माना नहीं वही, जलवायु परिवर्तन, प्रवास और खाद्य सुरक्षा से जुड़े युवा जागरूकता कार्यक्रमों के लिए एक स्वीडिश दानदाता द्वारा दिए गए 4.93 लाख रुपये के फंड पर भी खर्च खड़े किए गए।

कांग्रेस ने शुरू किया वोट चोर—गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। गुरुवार को कांग्रेस अर्यक विश्वनाथ चौधरी की अध्यक्षता में पार्टी नेताओं की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश नेतृत्व के आभारन पर लिले में वोट चोर—गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान जिले के सभी मंडलों, ब्लॉकों, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में एक साथ चलाया जायेगा।

कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि नेता प्रतिष्ठित राहुल गांधी ने वोट चोरों के आरोपों को लेकर साक्ष्य के साथ देश के लोगों को अपनी बात रखी थी। इसका बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर देशभर में भीम बहस छिड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को हाईजेक करने की सुनिश्चितता कोशिश की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता इसका पदाधिकार करेंगे।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले मांग पत्र पर हस्ताक्षर करवा देंगे। इस मांग पत्र में मशीन-रीडबल वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करना, जोड़े और हटाए गए मतदाताओं की फोटो सहित सुविधा जारी करना, एक सुलभ शिकायत निवारण प्रणाली लागू करना और मतदाताओं से दमन में शामिल आदि

विवाहिता के अपहरण का प्रयास एसपी से लगाया न्याय की गुहार

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। लालगंज थाना क्षेत्र की कुछुआदे निवासीनी मनु पत्नी अजीत ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर अपहरण जान माल के खा की गुहार लगाया है। एसपी को दिये पत्र में है। न के कह है कि उसकी ससुराल के लोग उधर दहेज के लिये कुमार—पीटते थे, इसकी शिकायत पर सात, सुनील, पति, नन्दन और छिन्नेपाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया। इससे नाराज होकर छिन्नेपाल द्वारा उसकी हत्या का कई बार प्रयास किया जा चुका है।

लालगंज थाना क्षेत्र की अजीत ने एसपी को पत्र देकर छिन्नेपाल, उनके भाई मनु पत्नी पुष्पा, रामनरेश के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने के साथ ही अपने जान माल के खा की गुहार लगाया है।

लालगंज थाना क्षेत्र की अजीत ने एसपी को पत्र देकर छिन्नेपाल, उनके भाई मनु पत्नी पुष्पा, रामनरेश के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने के साथ ही अपने जान माल के खा की गुहार लगाया है।

प्रभारी मंत्री ने किया विकास योजनाओं की समीक्षा

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। प्राथमिक, शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। इस अवसर पर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं सभी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ना. मंत्री ने जनपद में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों एवं सुरक्षा व्यवस्था की विस्तारपूर्वक समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय से प्रब्रंधक मसीहजुजमा के साथ सोसायटी का कामला: जिला विद्यालय निरीक्षक से का हस्ताक्षर प्रमाणित करने की मांग

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। चौर इन्टरमीडियट इन्स्टीट्यूट ससायटी के अध्यक्ष मसीहजुजमा ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र देकर अध्यक्ष का हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाने की मांग किया है जिससे उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का अनुपालन हो सके।

पत्र में कहा गया है कि नियत प्राधिकारी उप जिलाधिकारी बस्ती सदर ने मसीहजुजमा के प्रबन्ध 1 समिति को वेब घोषित किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती ने बिना प्रबंधक मसीहजुजमा को सुने एक पक्षीय आदेश पारित किया गया था उसे 17 सितम्बर 2025 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की एकल पीठ ने खगान आदेश दे दिया। इसके पूर्व प्रबंधक मसीहजुजमा द्वारा विद्यालय में 21 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी जो शासनार्थ दिनांक 12-3-2018 के विरुद्ध था, उसे भी उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अवैधानिक एवं अनियमित मानते हुये निरुक्ति को अवैध मानते हुये खाली कर दिया गया। निरुक्ति के सम्बंध में शासन स्तर पर जांच हो रही है।

भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष आर.के. आरतियन के पुलिसिया पिटाई का मामला गरमाया

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। भारत मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष आर.के. आरतियन को लालगंज थाना क्षेत्र के सिद्धनाथपुर गांव में हुई नाबालिग दलित बालिका की निर्मम हत्या मामले में सिविल लाइन्स चौकी इन्चार्ज अजय सिंह द्वारा भारी पीटने, जेल भेजवा देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के लोग जुटे और मांग किया कि चौकी इन्चार्ज अजय सिंह के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही एसपीएफ की मुकदमा दर्ज कराते हुये निलम्बित किया जाय। अपनी मांग को लेकर डीएम कार्यालय की ओर जाते समय प्रशासन ने उन्हें बड़े वन के निकट ही रोक दिया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला प्रभारी राम सुमेर यादव के नेतृत्व में आयोजित आन्दोलन के दौरान जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन न्याय विलासदर को सौपा गया। चेलावती दी गई कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई न किया तो चरमवाद आन्दोलन जारी रहेगा। घटना को लेकर सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के नेताओं में आक्रोश है।

ज्यापन ने सिविल लाइन्स चौकी इन्चार्ज अजय सिंह को निलम्बित न किया जायों की दुर्गुणपूर्ण है। कहा कि दुर्गुणों की संज्ञा फार्मासिस्टों का धर्म है। फार्मासिस्टों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्टों की मानक के अनुरूप नियुक्ति के साथ ही संस्था के अनुरूप उसकी सहायता की जानी चाहिये।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से जय प्रकाश मौर्य, दुर्गा गुप्ता, मे.अलम, विनोद कुमार, श्याम प्रकाश शर्मा, बी.एन. सुक्ल, श्याम नारायण चौधरी, संदीप कुमार, गंगाराम, मधु प्रकाश, रामजीत यादव, सिकार चौहान, संजय गुप्ता, सौरभ पाण्डेय, सुधाश्र मिश्र, मोहित साहू, अनिल कुमार चौधरी, रामनरेश गुप्ता, रामनरेश यादव, मनोज गुप्ता, चन्द्रजीत यादव, हरि कलश, चण्णयाम शर्मा, आदर्श धर्म, रवि विश्वकर्मा, विक्रान्त यादव, मे.अ. आशरफ, अजित श्रीवास्तव के साथ ही अनेक फार्मासिस्ट एवं सामाजिक संगठनों के लोग उपस्थित रहे।

टेट अनिवार्यता के विरोध में जारी है शिक्षकों का हस्ताक्षर अभियान

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। टेट की अनिवार्यता को लेकर सौदा न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षकों का आन्दोलन परबन्धक ढंग से जारी है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल ने बताया कि अधिनियम प्राथमिक शिक्षक संघ राष्ट्रीय नेतृत्व के आवाहन पर शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही 24 दिसम्बर को शिक्षकों को निलम्बित में शोषण अध्यक्ष, मंत्री और पदाधिकारी प्रतिनिधित्व—एक न्याय पंचायत के शिक्षकों का हस्ताक्षर करा रहे हैं। हस्ताक्षरित ज्ञापन में मेल आई.डी. के माध्यम से राष्ट्रीय, सौदा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और वैसिक शिक्षा मंत्री को भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल ने बताया कि शिक्षकों को निलम्बित में शोषण अध्यक्ष, मंत्री और पदाधिकारी प्रतिनिधित्व—एक न्याय पंचायत के शिक्षकों का हस्ताक्षर करा रहे हैं। हस्ताक्षरित ज्ञापन में मेल आई.डी. के माध्यम से राष्ट्रीय, सौदा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और वैसिक शिक्षा मंत्री को भेजा जा रहा है।



और पारदर्शी तरीके के साथ पहुंचाया जाय। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी समस्त योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को युद्ध स्तर पर दिया जाय। आम जनमानस की सेवा ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पात्र आम जनमानस के साथ किसी भी स्तर पर लापरवाही को गड़बड़ाव किया जाय।

मामला: जिला विद्यालय निरीक्षक से का हस्ताक्षर प्रमाणित करने की मांग



—21 शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त होने के बाद तूल पकड़ने लगा है मामला

इस प्रकरण में उप जिलाधिकारी सदर बस्ती ने अपने आदेश में कहा है कि मुस्ताक अहमद खान की मृत्यु के विरुद्ध था, उसे भी उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अवैधानिक एवं अनियमित मानते हुये निरुक्ति को अवैध मानते हुये खाली कर दिया गया। निरुक्ति के सम्बंध में शासन स्तर पर जांच हो रही है।

भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष आर.के. आरतियन के पुलिसिया पिटाई का मामला गरमाया



—दोषी दारोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर निलम्बन की मांग: सौपा ज्ञापन

के मामले में मुकदमा पंजीकृत कर कड़ी कार्रवाई की मांग किया गया है। बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष हनुमान प्रसाद, मण्डल अध्यक्ष गणेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष बुद्धेश्वर राना, भारत मुक्ति मोर्चा महिला जिलाध्यक्ष सारिता भारती, सया नेता शक्ति कुमार, अंकुश गुप्ता आदि ने ज्ञापन देने के पूर्व चेतावनी दिया गया कि यदि दोषी दारोगा अजय सिंह के विरुद्ध कार्रवाई न हुई तो पूरा आन्दोलन किया जायेगा। कहा कि न्याय के लिये अवाहन उठाते पर पुलिसिया दमन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जिला प्रशासन दोषी दारोगा अजय सिंह के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई करे। भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष आर.के. आरतियन ने कहा कि प्रशासन और शीघ्र दोषी दारोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर निलम्बन की मांग: सौपा ज्ञापन



प्रवक्ता सूर्य प्रकाश शुक्ल के नेतृत्व में 15 बकटी में नवीन कुमार के नेतृत्व में 37, रामनरेश अखंड इन्स्टेन के नेतृत्व में 14, गौर में जिला संचालन मंत्री बाला अखंड देवगंज में 15 शिक्षकों के हस्ताक्षर किया गया। शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा, सात पदाधिकारी विद्यालयों में जाकर हस्ताक्षर करा रहे हैं।

"युद्धो अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

दैनिक

भारतीय बस्ती

बस्ती 26 सितम्बर 2025 शुक्रवार

सम्पादकीय

लद्दाख में हिंसा

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा देने व संविधान के अंतर्गत विशेष संरक्षण देने वाली छठी अनुसूची में शामिल करने के लिये चल रहे आंदोलन का हिंसक होना दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बीते पंद्रह दिनों से अनशन पर थे। इन्हीं मुद्दों के समर्थन में यह आंदोलन चल रहा था। हालांकि, हिंसा के बाद उन्होंने अपना अनशन त्याग दिया है। उन्होंने आंदोलनकारियों से शांति की अपील की है। हिंसा व आगजनी के बाद केंद्र शासित प्रदेश में संचारबंदी लागू की गई है। समाचार माध्यमों में कुछ आंदोलनकारियों के मारे जाने की बात भी कही जा रही है। उल्लेखनीय यह है कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्रशासित प्रदेश में लद्दाख को पूर्ण राज्य देने की मांग को लेकर समय-समय पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। बताया जाता है कि पिछले पैंतीस सालों से कुछ लोग अनशन कर रहे थे। परसें उनमें से दो लोगों की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद लोगों में आक्रोश बढ़ा। प्रतिक्रिया स्वरूप लेह बंद का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। यह प्रदर्शन कालांतर हिंसक प्रतिरोध में बदल गया। घटनाक्रम के बाद जम्मू-कश्मीर के विपक्षी दलों ने हिंसा के लिये केंद्र को निशाने पर लिया है। कहा गया कि आंदोलनकारी लेह की अस्मिता को संरक्षण देने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र व लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच आगामी माह में एक वार्ता का दौर निर्धारित था, लेकिन आंदोलनकारी इससे पहले ही इस दिशा में पहल की मांग करते रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के विपक्षी दलों के नेता लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद लोकों का आक्रा पूर्ण न होने पर उपजे आक्रोश को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि लेह के लोग आरू वायदों से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से आंदोलनकारियों की हिंसक अभिव्यक्ति सामने आई है।

जम्मू-कश्मीर के विपक्षी नेताओं द्वारा सवाल उठाये जा रहे हैं कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने पर जश्न मनाने वाले लद्दाख के लोगों में आज आक्रोश क्यों पनप रहा है? वे इस अभिव्यक्ति के आलोक में जम्मू-कश्मीर के राज्य के लेह को फिर वापस लौटने की भी मांग कर रहे हैं। निस्संदेह, देश की सभी की सीमा से लगा सुखा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है, जिसके मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि लेह के आंदोलनकारी कई सालों से भीम संरक्षण व संस्कृति की रक्षा के लिये इस केंद्रशासित प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची का कवच देने तथा पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। उनका कहना था कि केंद्र शासित प्रदेश बनने से क्षेत्र के लोगों की आंकाखा पूरी नहीं हुई। एक बड़ा मुद्दा क्षेत्र के युवाओं की बेरोजगारी रही है। युवाओं की दलील है कि क्षेत्र के युवाओं को पहले जम्मू-कश्मीर पुलिसक सॉर्विस सेलेशन कमीशन में राजपत्रित अधिकारी पदों के लिये आवेदन का मौका मिलता था, जो लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बंद हो गया। स्थानीय युवा अब केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की स्पर्धा में टिक पाने में दिक्कत महसूस करते हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय नौकरियों में युवाओं के लिये कोई विशेष अभियान भी नहीं चला। जिससे बेरोजगारी में ख़ासा रोक व्याप्त रहा है। वहीं लद्दाख की अस्मिता को संरक्षित करने के लिये छठी अनुसूची का मांग लंबे समय से की जाती रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भाजपा ने वर्ष 2019 के घोषणापत्र में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने का वायदा किया था। लेकिन अब इस पर आनाकानी की जा रही है। आंदोलनकारी इसके अलावा कारगिल व लेह को लोकसभा सीट बनाने और स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने की भी मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 244 की छठी अनुसूची में ऐसी स्वायत्त व अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक इकाइयों का प्राधान्य है, जिनके पास जल-जंगल व उद्योगों को लेकर क्षेत्र की संस्कृति व संरक्षण हेतु निर्णय करने का अधिकार होता है।

—अभिनव आकाश—

चीन भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश तो कर रहा है, अगर फौरी तौर पर देखें तो ऐसा ही कुछ फिल गुड सिचुएशन नजर आया। लेकिन चीन की मंशा को लेकर स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हमेशा भारत को आगाह और सचेत करते रहे हैं। चीन पर मरोसा नहीं किया जा सकता। इसके पीछे 1962 वाली घटना का भी जिक्र किया जाता है। हिंदी-चीनी भाई-भाई की आड़ में दगाबाजी का खंजर चीन के द्वारा भारत की पीठ पर घोपा गया था। चीन ने भारत पर हमला किया और आज भी हमरी 38-39 हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमाव बैठा है। चीन ने ऐसी ही नौकाम 2020 में भी की। कोरोना नामक महामारी से हैरान-फेरान दुनिया इससे इलाज तलाश रही थी लेकिन मक्कावा चीन इसकी आड़ में भारत की जमीन को हथियाने की कोशिश की। नतीजन गलवान घाटी में डूंगन के नापाक मंसूबों के आगे हिंद की सेना मजबूती के साथ डट खड़ी हुई।

वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार इसमें चीन की पीएचए को शहादत झेलनी पड़ी। हालांकि इस ब्रह्म में भारत के सैनिक भी शामिल

बंजर भूमि पर हो प्राकृतिक खेती

—उमेश चतुर्वेदी—

देश में खेती की जमीन घट रही है या बढ़ रही है, इसे लेकर दो तरह की बातें की जा रही हैं। एक वर्ग का मानना है कि देश में खेती की जमीन बढ़ रही है। हालांकि जिस तरह शहरीकरण बढ़ रहा है, खासकर उपजाऊ जमीनों पर शहरों का निर्माण हो रहा है, उससे लगता तो नहीं कि खेती की जमीन बढ़ रही है। हालांकि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लोकमान्य में पेश एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2018-19 में जहां 180624 हजार हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है, वहीं साल 2021-22 में बढ़कर 219158 हजार हेक्टेयर हो गई है। इससे तो हमें खुश होना चाहिए। क्योंकि चीन जैसे देश अपने यहां खेती योग्य जमीन की कमी को लेकर चिंतित हैं।

लेकिन एक और रिपोर्ट आई है, लैंड यूज ट्रेडिस्टिकस एफ ए रैंस 2012-13 डू 2021-22 इस रिपोर्ट का कहना है कि कहती है, 2018-19 से 2021-22 तक खेती योग्य जमीन का वार्षिक घटकर 180.62 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 180.11 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। यह रिपोर्ट राज्यों को सूझाती है कि औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों आदि के लिए वे बंजर भूमि का उपयोग करें। संक्षिप्त रूप में संतुष्टिक, भारत में भूमि राशय सूची का विषय है। इसलिफ राज्यों पर इसके लिए देवाव नहीं बनाया जा सकता। लेकिन दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि के विकास को देखने से पता चलता है कि भारी मात्रा में खेती योग्य और बेहद उपजाऊ जमीन अब कमी के उंगल में बदल चुकी है। शायद यही वजह है कि अब बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने को लेकर मांग उठने लगी है।

भारत में कुल 14 करोड़ हेक्टेयर पर नियमित खेती होती है। आज खेती की जो हालत है, जिस तरह जलमय कीटनाशकों और रासायनिक खादों का इस्तेमाल बढ़ा है, उसकी वजह से खेती की मिट्टी भी खराब हो चुकी है। अब कैसर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के लिए विशेषज्ञ रासायनिक खाद और कीटनाशक युक्त खेती को भी जिम्मेवार बताया जा रहा है। पंजाब के बल्लड या राजस्थान के जोधपुर के लिए चलने वाली विशेष डूने को कैसर देई इसलिफ कहा जाने लगा है, क्योंकि इससे ज्यादातर यात्री जोधपुर के कैसर अस्पताल में अपना इलाज करवाते जाते हैं। जाने वाले खेती की उपज के लिए महशूर पंजाब राज्य के लोग हो रहे हैं। इसी लिए अब प्राकृतिक, जैविक या नो बजट खेती की मांग बढ़ रही है। इस खेती के जरिए होने वाली उपज को स्वास्थ्य बर्क माना जाने लगा है। लेकिन खेती की मौजूदा जमीन को सुधारने एक दिन का काम नहीं है और उरचें सुधारने में बहुत बल लगना। इसलिए अब हमें हमने होने है कि भारत में जो पॉजिटिव लैंड या बंजर जमीन है, उसे तैयार करके उस पर प्राकृतिक और जैविक खेती करने के



हुए। कुल मिलाकर कहे कि अगर जानकार चीन पर मरोसे की बात को लेकर हमेशा आगाह करते रहते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी है। चीन की साजिशों को बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले अब तिब्बत सरकार के पूर्व राष्ट्रपति तिब्बत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. लोसांग सांगे ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो बिल्कुल चौंकाते वाले हैं।

उनका कहना है कि चीन की चालें केवल सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। बल्कि सीधे भारत की सत्ता

पर वार करने लगी है। उनका ये कहना है कि दिल्ली स्थित चीनी दूतावास न केवल भारतीय नेताओं और पत्रकारों को सभाने की कोशिश कर रहा है, जिनमें यूट्यूबर्स भी शामिल हैं। उनके सहारे मोदी सरकार के तख्तापलट किया जा रहा है। चीनी दूतावास इस कोशिश में है कि मांदा सरकार का तख्तापलट किया जाए और इसके लिए वो कई तरह के प्लडन रच रहे हैं। मीडिया का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कई बड़े

पत्रकार समेत कई यूट्यूबर्स शामिल हैं। सारे दावे तिब्बत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. लोसांग सांगे ने एक इंटरव्यू के दौरान किए हैं।

पत्रकारों को प्रभावित करने, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी लालच दिया जा रहा है। मीडिया में पैसा डालकर

नैस्टिड को बदलने का खेल बीजिंग खेल खेल रहा है। भारत के पड़ोस पर नजर डालेंगे तो चीन के पड़ोस के कुछ सरकारें खड़ी हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश इसका उदाहरण हैं। बीजिंग का खेल सिर्फ व्यापार

नहीं है बल्कि इसकी आड़ में सत्ता पकड़ने की भी खेलता है। ऐसा ही खेल वो भारत में भी खेलने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने बताया कि कैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव और पाकिस्तान में चीन ने सत्ताधारी वर्गों को अपने पक्ष में किया। उनके शब्दों में ये एलीट कैम्बर की मिसाल है। डॉक्टर सांगे ने ये भी बताया कि ये रणनीति दक्षिण एशिया से आगे तक फैली है। उन्होंने कहा कि मैंने यूरोप में ऐसे मंत्री देखे हैं जिन्होंने चीन की तारीफ की और बाद में चीनी कर्पनियों में डायरेक्टर और यह 100,000 डॉलर से लेकर 888,000 डॉलर तक की सालाना तनख्वाह पर। डॉक्टर सांगे ने भारत के सभी दलों के नेताओं, व्यापारियों और पत्रकारों को अलर्ट रहने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि चीन को फर्क नहीं पड़ता कि वह किस खरीदता है, जब तक वह उनके एजेंडे को आगे बढ़ता है।

ऑ. सांगे ने आगे तर्क दिया कि बीजिंग के प्रभावकारी अभियान भारत को नियंत्रित करने के उसके व्यापक भू-राजनीतिक लक्ष्य से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि चीन मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का समर्थन क्यों कर रहा है? वे भारत पर हमला करने वाले आतंकवादियों

के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि वे भारत को घेरना चाहते हैं और दक्षिण एशिया पर अपना दबदबा बनाए चाहते हैं। चीन के आर्थिक प्रभाव की तुलना राजनीतिक चालाकी से करते हुए, उन्होंने भारत के व्यापार घाटे पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वेतुन हूहा कि भारत चीन से 113 अरब डॉलर का सामान खरीदता है, लेकिन केवल 14 अरब डॉलर का बेचता है। यह 99 अरब डॉलर का घाटा है। इसका मतलब है कि भारत में कम कारखाने, कम विनिर्माण और कम नौकरियां होंगी। चीन के साथ जुड़ाव न केवल अस्तित्व है, बल्कि खतरनाक भी है।

ऑ. सांगे ने हैनरी किंसिंजर के उस लेखप्रिय सिद्धांत पर भी निशाना साधा कि चीन के साथ व्यापार से उसका लोकतांत्रिकरण होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम ने 30 साल तक हिंदी अम में विवेक किया। लोकतांत्रिक बनने के बजाय, चीन और अधिक विरोधी हो गई है। मुझे उम्मीद है कि भारत यह गलती नहीं दोहराएगा। बहरहाल, सीमा पर पहले से ही तनाव चरम पर है, ऐसे में ऑ. सांगे के शब्द एक भयावह चेतावनी है कि चीन की भारत के लिए घुनापी सिर्फ सैन्य ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक भी है।

नवरात्रि, प्रसाद और पालन—पोषण



— डॉ. प्रियका सौरभ —

नवरात्रि, भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह केवल नौ दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह भक्ति, संयम, स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। नवरात्रियों के दौरान भक्त अपने घरों और मंदिरों में देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और भोजन खाते खाते—पान पर विशेष ध्यान देते हैं। हलवा—पूरी, चने की दाल, फल और अन्य पारंपरिक व्यंजन इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इन व्यंजनों का स्वादिष्ट और पवित्र होना उन्हें एक धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बनाता है। हालांकि, इस पर्व पर उरसा के बीच एक महत्वपूर्ण पहल उठता है—व्यायाम नवरात्रियों में बनाए जाने वाले व्यंजन केवल मानव उपभोग के लिए ही सुरक्षित है, या इन्हें हमारे पवित्र मित्र, जैसे गाय, को भी दिया जा सकता है? यह प्रश्न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और पारिस्थितिक संतुलन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

नवरात्रियों में हलवा—पूरी का प्रसाद मुख्य रूप से गेहूं के आटे, दूध और चीनी से तैयार किया जाता है। इसके स्वाद और सुगंध से भक्त आनंदित होते हैं और इसे देवी की भक्ति का प्रतीक मानते हैं। हलवा—पूरी का आनंद देना न केवल उत्सव का हिस्सा है, बल्कि यह पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करता है। हालांकि, इसके स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है।

इसानों के लिए हलवा—पूरी सीमित मात्रा में ऊर्जा और स्रोत प्रदान करती है। परंतु, अत्यधिक मात्रा में इसे खाना पाचन समस्याएं, वजन बढ़ाने और अन्य स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। नवरात्रियों के दौरान लोग अक्सर फल, हल्का सल्बिक भोजन और दूध जैसे चीजों का सेवन करते हैं। ताकि शरीर और मन दोनों को शुद्ध किया जा सके। इसलिए, हलवा—पूरी का सेवन संयमित और सोच-समझकर होना चाहिए।

अब सवाल उठता है कि क्या गाय को भी हलवा—पूरी दी जा सकती है। हिंदू धर्म में गाय को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे माता के दर्जा प्राप्त है और धार्मिक ग्रंथों में उनकी सेवा और संरक्षण का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन, गायों को पाचन तंत्र इंसानों से भिन्न होता है। वे मुख्य रूप से हरी घास, चारा, भूसा और अनाज पर निर्भर करती हैं। पी, चीनी और मैदा जैसी भारी और मोटी चीजें उनके लिए हानिकारक हो सकती हैं। हलवा—पूरी



में मौजूद अत्यधिक ची और चीनी उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इससे दस्त, अपच और अन्य पचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

यहां पर संतुलन की आवश्यकता स्पष्ट होती है। नवरात्रियों का उद्देश्य न केवल आस्था और भक्ति है, बल्कि पशुओं और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व बनाए रखना भी है। श्रद्धा और सुखा एक साथ चल सकते हैं। गायों के स्वास्थ्य के लिए हलवा—पूरी देना सही नहीं है, और उन्हें प्राकृतिक घास, हरी घास और अन्य पौधों से श्रद्धा का वास्तविक अर्थ यही है कि हम अपनी आस्था का पालन करते हुए भी विवेक का उपयोग करें।

पारंपरिक रूप से, नवरात्रियों में प्रसाद वितरण केवल मानव उपभोग तक सीमित होना चाहिए। ऐसा करने से धार्मिक आस्था का पालन होता है और पशुओं की सुखी भी सुनिश्चित होती है। कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों इस संतुलन को बनाए रखते हुए अपने प्रसाद में केवल फल, हरी पत्तियां और सुखा अनाज देते हैं। इससे गायों को पोषण मिलता है और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है।

संस्कृतिक दृष्टि से यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय परंपरा में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में उनका संरक्षण, सम्मान और सेवा विशेष रूप से उल्लेखित है। अगर हम नवरात्रियों में श्रद्धा और परंपरा का पालन करते हुए गायों के स्वास्थ्य की अंखड़ी देखेंगे, तो हम उनकी सुखा और सुख—पोषण के सिद्धांतों के प्रति उत्तरदायी नहीं रह पाएंगे। यह एक ऐसा मामला है जहां धर्म और विज्ञान का संतुलन आवश्यक है।

विज्ञान और जागरूकता इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धार्मिक आयोजकों, मंदिरों और परिवारों को यह समझना आवश्यक है कि उच्छेद द्वारा दिया जाने वाला प्रत्येक प्रसाद केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पशु सुसंभलित होना चाहिए। उच्छेद, सामाजिक संबंधों और धार्मिक समुदायों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि लोग समझ सकें कि हलवा—पूरी गायों के लिए सुरक्षित नहीं है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी यह मानते हैं कि गायों को इंसानों के खान—पान से अलग रखना उनके दीर्घकालीन

स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पी, चीनी और तेल से बनी चीजें उनके जठरांत्र प्रणाली में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इसलिए नवरात्रियों के दौरान पारंपरिक प्रसाद का आनंद केवल इंसानों के लिए ही लेना चाहिए। इससे धार्मिक आस्था भी नहीं रहती है और पशुओं की सुखा सुनिश्चित होती है।

नवरात्रियों में हलवा—पूरी का महत्व केवल स्वाद या परंपरा तक सीमित नहीं है। यह भक्ति, सामूहिक उत्साह और परिवार के साथ समय बिताने का माध्यम भी है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्रद्धा का अर्थ केवल परंपरा निमाना नहीं है, बल्कि इसमें विवेक और समझदारी भी शामिल होनी चाहिए। गायों और अन्य पालतू पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रसाद का वितरण किया जाना चाहिए।

अध्ययन और अनुभव बताते हैं कि धार्मिक आयोजनों में पशुओं की अलखड़ी प्रकृति से न केवल उनका स्वास्थ्य कमजोर होता है, बल्कि समाज में जागरूकता की कमी भी उजागर होती है। इसलिए, नवरात्रियों में पशु सुसंभलित और मानव स्वास्थ्य दोनों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इससे हमारी धार्मिक आस्था और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों पूरी होती हैं।

इस परंपरा के माध्यम से हम बच्चों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। उन्हें यह सिखाया जा सकता है कि धार्मिक पर्व केवल उत्सव और आनंद का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इसमें विवेक, जिम्मेदारी और सह-अस्तित्व का भी संदेश छिपा है। बच्चे जब यह सीखेंगे कि हलवा—पूरी केवल इंसानों के लिए है और गायों को प्राकृतिक घास दिया जाता है, तो वे अपने जीवन में भी संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। नवरात्रियों का संदेश यही है कि आस्था, संयम और विवेक एक साथ अपनाया जाए। पारंपरिक व्यंजनों और प्रसाद का आनंद लेते समय हम यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चार—पाँव वाले मित्रों की सुखा और स्वास्थ्य सुनिश्चित होना चाहिए। अगर हम यह संतुलन बनाए रखेंगे, तो नवरात्रियों का उत्सव और भी अर्थपूर्ण और सुखदायक बन जाएगा। यह याद रखना चाहिए कि नवरात्रियों का वास्तविक उद्देश्य केवल देना—पीने और उत्सव का आनंद नहीं है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि भक्त और विवेक साथ—साथ चल सकते हैं।

[illegible]

4